हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 183 लखनऊ, शनिवार 28 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी, सीबीआई को कोर्ट ने लगाई फटकार

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया है। इसके अलावा इस मामले में 21 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश करने में विफल रहा। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच में हुई चूक के लिए संघीय जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, जबकि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता था। उन्होंने कुछ भ्रामक कथनों पर जोर दिया और कहा कि विस्तृत आरोपपत्र में कई कमियां हैं जिनकी पुष्टि सबूतों या गवाहों से नहीं होती है। न्यायाधीश सिंह ने कहा, श्श्आरोपपत्र में आंतरिक विरोधाभास हैं, जो साजिश की थ्योरी की जड़ पर प्रहार करते हैं।श्श उन्होंने कहा कि किसी भी सबूत के अभाव में केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप टिक नहीं सकते और पूर्व मुख्यमंत्री को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि यह कानून के शासन के प्रतिकूल था। सिसोदिया के संबंध में न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उनकी संलिप्तता को दर्शाता हो और न ही उनसे कोई बरामदगी की गई है। यह मामला कथित अनियमितताओं से जुड़ी उस आबकारी नीति से संबंधित था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में अनियमितताएं हुईं और इसमें शीर्ष स्तर की भूमिका रही। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि गंभीर आरोपों के लिए मजबूत और ठोस साक्ष्य आवश्यक होते हैं, केवल अनुमानों या सामान्य आरोपों के आधार पर किसी को साजिश का मुख्य किरदार नहीं ठहराया जा सकता। आदेश में कहा गया कि बिना ठोस प्रमाण के केंद्रीय साजिशकर्ता की भूमिका तय करना कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकता। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाते समय जांच एजेंसियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिना पर्याप्त सबूत के दावे सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।

नेपाल चुनाव से पहले भारत–नेपाल सीमा 3 दिन बंद, 2 मार्च मिडनाइट से 5 मार्च तक कोई आवाजाही नहीं

बीएनई

बहराइच। नेपाल में पांच मार्च को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर भारत–नेपाल सीमा दो मार्च की आधी रात से पांच मार्च की आधी रात तक बंद रहेगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बहराइच के रुपईडीहा में स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) के प्रभारी सुधीर शर्मा ने बताया कि नेपाल के गृह मंत्रालय ने सीमा बंद करने के संबंध में 26 फरवरी को एक आधिकारिक पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और विश्वसनीय वातावरण में सुनिश्चित करने के लिए भारत से सटे बांके जिले के पूरे हिस्से की सभी सीमा चौकियां दो और तीन मार्च के दरमियान मध्यरात्रि 12 बजे से पांच मार्च की रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। शर्मा ने कहा कि इस अवधि के दौरान चौकी के माध्यम से वस्तुओं का आयात और निर्यात निलंबित रहेगा। हालांकि, आवश्यक दवाओं और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी। सशस्त्र सीमा बल की 42वीं बटालियन के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत ने कहा कि नेपाल प्रशासन की ओर से जारी एक पत्र के बाद दो मार्च की आधी रात से पांच मार्च को मतदान की रात तक सीमा पर श्सीमित आवाजाहीश की व्यवस्था को लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर पहले से ही अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और पहचान दस्तावेजों की गहन जांच और सत्यापन के बाद ही लोगों को सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

नौसेना में शामिल आईएनएस अंजदीप, एंटी–सबमरीन वॉरफेयर की क्षमताओं को बढ़ाएगा

एजेंसी

चेन्नई। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को आईएनएस अंजदीप युद्धपोत का जलावतरण किया। इस युद्धपोत का उद्देश्य भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं और तटीय निगरानी को बढ़ाना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने चेन्नई बंदरगाह पर पोत का जलावतरण किया। आईएनएस अंजदीप श्एंटी–सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्टश परियोजना के तहत बनाए जा रहे आठ पोतों में से तीसरा है। यह पोत डॉल्फिन हंटर के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें नष्ट करना है। चेन्नई बंदरगाह पर आयोजित एक आधिकारिक समारोह में एडमिरल त्रिपाठी ने नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से पोत का जलावतरण किया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 77 मीटर लंबे इस पोत में एक हाई–स्पीड वाटर–जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है जो इसे त्वरित प्रतिक्रिया और निरंतर संचालन के लिए 25 समुद्री मील की अधिकतम गति हासिल करने में सक्षम बनाता है।

कोलकाता समेत कई जिलों और बांग्लादेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके

एजेंसी

कोलकाता। बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में 5.5 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किए जाने के बाद कोलकाता और आसपास के जिलों में शुक्रवार दोपहर झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने कहा कि भूकंप दोपहर एक बजकर 22 मिनट पर महसूस किया गया। उन्होंने कहा कि भूकंप धरती की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया था।

निवेश और नवाचार के साथ आगे आए उद्योग, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कंपनियों से बजट में हुई घोषणाओं का लाभ उठाने का किया आग्रह

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय उद्योग से निवेश एवं नवाचार बढ़ाने का शुक्रवार को आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आक्रामक पूंजीगत व्यय और बजट में लगातार अनुकूल नीतिगत माहौल बनाकर आधार तैयार कर दिया है और अब निजी क्षेत्र के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वृद्धि के अगले चरण को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त विषय पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026–27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है। उन्होंने कहा कि अधिक आवंटन निजी क्षेत्र को नए जोश के साथ निवेश करने और 2026–27 के बजट घोषणाओं का लाभ उठाने का संकेत देता है। मोदी ने कहा, भारतीय कंपनियों को नए निवेश एवं नवाचार के साथ आगे आना चाहिए। वित्तीय संस्थानों को व्यावहारिक समाधान तैयार करने और बाजार विश्वास बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने सुधारों को ठोस परिणामों में तब्दील करने के लिए सरकार, उद्योग और ज्ञान क्षेत्र के भागीदारों के बीच घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। मोदी ने कहा, हमें अवसंरचना में अधिक भागीदारी एवं वित्तीय मॉडल में नवाचार की आवश्यकता है... हमें परियोजना स्वीकृति पद्धतियों को मजबूत करना चाहिए और मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। सरकार ने पिछले एक दशक में भारत की वृद्धि रणनीति को रिकॉर्ड स्तर के पूंजीगत व्यय के इर्द–गिर्द केंद्रित किया है। निजी निवेश को आकर्षित करने और मध्यम अवधि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, डिजिटल अवसंरचना तथा ऊर्जा नेटवर्क पर व्यय में तेज वृद्धि की गई है। हालांकि, निजी क्षेत्र ने अभी तक वह तथाकथित जुझारूपन (एनिमल स्पिरिट) पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं किया है। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में भारत की मजबूत क्षमता दृढ़ विश्वास–आधारित सुधारों और कारोबार सुगमता में निरंतर सुधार के प्रयासों से प्रेरित रही है। भारत ने प्रौद्योगिकी–आधारित सुशासन को अपनाया है, संस्थानों को मजबूत किया है और आज भी देश सुधारों के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने कहा, सुधारों की तेज गति को बनाए रखने के लिए हमें केवल नीतिगत मंशा पर ही नहीं, बल्कि उत्कृष्ट क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होगा। सुधारों का मूल्यांकन उनके जमीनी प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हमें कृत्रिम मेधा, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के तहत सरकार, उद्योग, वित्तीय संस्थानों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए रिफॉर्म पार्टनरशिप चार्टर बनाने का प्रस्ताव रखा। मोदी ने कहा कि जब सरकार, उद्योग और ज्ञान क्षेत्र से जुड़े लोग एक साथ आते हैं, तो सुधार परिणामों में बदलते हैं और कागज पर की गई घोषणाएं जमीनी स्तर पर उपलब्धियों में तब्दील होती हैं। सरकार द्वारा घोषित निवेशक–हितैषी नीतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ढांचे को सरल बनाया गया है और अधिक पूर्वानुमेयता लाई गई है। इसके अलावा, बॉन्ड बाजार को गहरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सतत विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कम जोखिम वाले नए वित्तीय साधन विकसित किए जाने चाहिए। बजट का मूल्यांकन अक्सर विभिन्न मानकों पर किए जाने का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा, राष्ट्रीय बजट कोई अल्पकालिक व्यापारिक दस्तावेज नहीं है। यह एक नीतिगत खाका है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस एवं सार्थक मानकों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हर वर्ष बजट के बाद आयोजित होने वाला बजट वेबिनार महत्वपूर्ण होता है। मेरी इच्छा है कि यह वेबिनार केवल औपचारिक विचार–विमर्श तक सीमित न रहे, बल्कि सार्थक मंथन पर केंद्रित हो।

मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली नौकरी पर सख्त आदेश, अब तीन माह में करना होगा निस्तारण

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दिए जाने वाले सेवायोजन (कंपैशनेट अपॉइंटमेंट) के मामलों में हो रही देरी पर सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की ओर से जारी शासनादेश में निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी प्रकरणों का निस्तारण अधिकतम तीन माह के भीतर पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। कार्मिक अनुभाग–2 की ओर से जारी आदेश सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (यथासंशोधित) नियमावली–1974 का उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक संकट से उबारना है। शासन के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जिससे आश्रित परिवारों को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नियमावली के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण किया जाए।

राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रचंड हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान, भारत–पाक सीमा पर सह–पायलट बन रचा इतिहास

बीएनई

जैसलमेर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को राजस्थान के जैसलमेर में स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। राष्ट्रपति ने भारत–पाकिस्तान सीमा के पास हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में सह–पायलट के तौर में उड़ान भर कर इतिहास रच दिया है। द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में सह–पायलट बनकर उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। एलसीएच प्रचंड ने जैसलमेर स्थित भारतीय वायु सेना (आईएएफ) स्टेशन से उड़ान भरी। उड़ान से पहले कैप्टन ने राष्ट्रपति को जानकारी दी। जैतून के हरे रंग की वर्दी और हेलमेट पहने हुए उन्होंने प्रस्थान करने से पहले कॉकपिट से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ने उड़ान के दौरान कॉकपिट से राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, प्रचंड हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का एक सशक्त प्रतीक है। इस समय मैं जैसलमेर जिले के ऊपर उड़ान भर रही हूं। मैं हमारे वीर सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। आपको मेरा सादर सलाम। जय हिंद, जय भारत। यह उड़ान लगभग 25 मिनट तक चली। हेलीकॉप्टर पोखरण फायरिंग रेंज के ऊपर से गुजरा, जहां भारतीय वायुसेना शाम को 'वायु शक्ति' नामक अग्नि शक्ति प्रदर्शन आयोजित करेगी। राष्ट्रपति मुर्मू दिन–दुशाला–रात्रि प्रदर्शन का भी अवलोकन करेंगी। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने राष्ट्रपति का जैसलमेर वायु सेना स्टेशन पर स्वागत किया।आज की इस उड़ान के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आक्रमण हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। यह राष्ट्रपति द्वारा अग्रिम मोर्चे के सैन्य प्लेटफॉर्म के साथ उच्च–स्तरीय सहभागिता की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने पिछले वर्ष अक्टूबर में अंबाला वायुसेना स्टेशन पर राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी, जिससे वह भारतीय वायुसेना के दो अलग–अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनीं। अप्रैल 2023 में उन्होंने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई–30 एमकेआई लड़ाकू विमान में लगभग 30 मिनट की उड़ान भरी थी। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी के ऊपर से उड़ान भरते हुए हिमालय का दृश्य भी देखा। एलसीएच 'प्रचंड' भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने निर्मित किया है। उन्नत एवियोनिक्स, स्टील्थ विशेषताओं, नाइट–विजन–अटैक क्षमता और एयर–टू–ग्राउंड व एयर–टू–एयर मिसाइलों, रॉकेट तथा 20 मिमी गन सहित शक्तिशाली हथियारों से लैस एलसीएच भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है।

नेपाल भाग रहे टेरर फंडिंग के आरोपी को एटीएस ने किया गिरफ्तार, अल्तमश फरीदी तुर्किए से मंगा रहा था रकम

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। तुर्किए से टेरर फंडिंग के लिए रकम मंगवाने वाले अमरोहा निवासी अल्तमश फरीदी को यूपी एटीएस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। वह नेपाल भागने की फिराक में था। इससे पहले एटीएस ने उसके साथी दिल्ली निवासी फरहान नबी सिद्दीकी को भी बीती 7 नवंबर को नोएडा से गिरफ्तार किया था। एटीएस ने इस प्रकरण की एफआईआर भी दर्ज की थी। एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि फरहान नबी से पूछताछ और जांच में अमरोहा के रजबपुर निवासी अल्तमश फरीदी का नाम सामने आया था। फरहान और अल्तमश ने तुर्किए में श्एचईवाईडीश नाम से एक वेबसाइट बनाई थी, जिसके जरिए तुर्किए के नागरिकों से कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए धन जुटाया जाता था। आरोपियों के बैंक खातों का इस्तेमाल तुर्किए से हवाला एवं अन्य माध्यमों से आये धन को मेसर्स इस्तानबुल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों एवं अन्य आरोपियों के खातों में घुमाने करने के लिए किया जा रहा था। बाद में इसका इस्तेमाल भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने तथा विभिन्न समूह के बीच धार्मिक वैमनस्यता एवं शत्रुता फैलाने के आशय से भड़काऊ इस्लामिक साहित्य बांटने में होता था। अल्तमश रजबपुर में एक अवैध मदरसे की स्थापना में भी शामिल था, जिसका उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।

केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने से जांच एजेंसियों की मनमानी उजागर हुई : महबूबा मुफ्ती

एजेंसी

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं को अदालत द्वारा बरी किए जाने से जांच एजेंसियों की मनमानी उजागर हुई है। मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट किया, आज के फैसले में केजरीवाल, (पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष) सिसोदिया और कविता (भारत राष्ट्र समिति की निलंबित नेता) को आबकारी शुल्क नीति मामले में बरी किए जाने से जांच एजेंसियों की मनमानी उजागर होती है।

10 वीं की छात्रा ने बोर्ड परीक्षा के दौरान शौचालय में बच्चे को दिया जन्म, मचा हड़कंप

बीएनई

धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा दे रही 17 साल की एक लड़की ने समय पूर्व बच्चे को जन्म दिया। छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारुल बेलापुरकर ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना पीथमपुर शहर के एक निजी स्कूल में हुई जब छात्रा मंगलवार को गणित विषय की परीक्षा दे रही थी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किशोरी ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की और शौचालय जाने की अनुमति मांगी। अधिकारी ने बताया कि जब वह काफी देर तक कक्षा में वापस नहीं आई, तो परीक्षकों ने शौचालय में देखा जहां उन्हें नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. प्रशांत कजावे ने बताया कि महिला कर्मचारी मौके पर पहुंचीं और लड़की तथा बच्चे को 108 एम्बुलेंस से सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उन्होंने कहा कि किशोरी और बच्चे दोनों की हालत स्थिर है। कजावे ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि लड़की को 34 हफ्ते (आठ महीने) का गर्भ था और बच्चे का जन्म समय से पहले हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस संबंध में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और मामला बेटमा थाने को स्थानांतरित कर दिया गया है। किशोरी ने बेटमा पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि वह एक नृत्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान एक लड़के से मिली थी और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। अधिकारी ने कहा कि छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि लड़के ने उसे चुप रहने की धमकी दी थी और इसलिए उसने अपने माता–पिता को दुष्कर्म के बारे में नहीं बताया। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

यूपी से फरार आर्थिक अपराधी राशिद नसीम यूएई में गिरफ्तार, ईडी के अनुरोध पर हुई कार्रवाई

एजेंसी

नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए निवेश धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े आर्थिक अपराधी राशिद नसीम को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। लखनऊ स्थित विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने पिछले साल अप्रैल में रियल एस्टेट फर्म शाइन सिटी समूह के प्रवर्तक नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत अपराधी घोषित किया था। यह जांच धनशोधन रोकथाम के एक मामले से संबंधित है। नसीम और लखनऊ स्थित शाइन सिटी समूह की कंपनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 554 मामलों का संज्ञान लेने के बाद ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी वाली रियल एस्टेट योजनाओं और श्मल्टी–लेवल मार्केटिंगश के माध्यम से उच्च मुनाफे के वादे के साथ 800–1000 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की गई। अधिकारियों ने बताया कि यूएई अधिकारियों ने नसीम को दुबई में गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उसके खिलाफ यूएई के अधिकारियों को एक डोजियर सौंपा था। अधिकारियों ने कहा कि इस फाइल में भारत में उसके खिलाफ चलाई गई पीएमएलए और एफईओए की कार्यवाही का विवरण था। इससे पहले जारी एक बयान में एजेंसी ने कहा था।

संपादकीय

विदेश नीति को बदलते प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इतिहास में अपना नाम किन अक्षरों में दर्ज कराना चाहते हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन भारत की विदेश नीति का जो गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसे वो पूरी तरह मटियामेट करना चाहते हैं, यह साफ नजर आ रहा है। वैसे भी जब इतिहास की पूरी समझ न हो, या जानबूझकर इतिहास को नजरंदाज किया जाता है तो वर्तमान और भविष्य दोनों किस तरह खतरे में पड़ जाते हैं, इसका बड़ा उदाहरण नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा से मिल ही रहा है। महज दो दिनों के लिए मोदी इजरायल गए, लेकिन वहां जो कुछ उन्होंने कहा, उससे भारत की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया है। बुधवार को इजरायली संसद नेसेट में जिस तरह का भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, उसमें वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि इजरायल ने फिलीस्तीन में हमास को खत्म करने के नाम पर जो नरसंहार किया, उस पर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इजरायली संसद में जाकर हमास की न केवल आलोचना की, बल्कि तीन साल पहले 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की तुलना भारत में मुंबई के आतंकी हमले से कर दी। माना कि दोनों में निर्दोष लोगों की ही जान गई, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि नरेन्द्र मोदी को यूपीए सरकार में हुआ मुंबई हमला अगर याद आया तो खुद की सरकार में हुए पुलवामा और पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमलों को वो कैसे भूल गए। होता तो यही है कि इंसान को हाल की बात पहले याद आती है और पुरानी बात बाद में। लेकिन मोदीजी के साथ उल्टा ही हो रहा है। उन्हें अपने कार्यकाल का कुछ याद नहीं रहता, केवल कांग्रेस की सरकारों की बातें याद पड़ती हैं। अपने संबोधन में मोदी ने गजा शांति पहल को क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक रास्ता बताया। यानी सीधे–सीधे अमेरिका की तारीफ उन्होंने की। इसके साथ ही इजरायल के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि कहीं भी आतंकवाद शांति को हर जगह खतरे में डालता है। गौर कीजिए कि मोदी ने इजरायल की कुर्बानियों का जिक्र किया लेकिन गजा में मारे गए 70 हजार लोगों की हत्या और हमदर्दी के लिए एक शब्द नहीं कहा, वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें तो ट्रंप और नेतन्याहू से दोस्ती निभानी है। मोदी ने गजा नरसंहार को पूरी तरह नजरन्दाज किया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन दुख इस बात का है कि अपने साथ–साथ उन्होंने पूरे देश की जनता को इजरायल के साथ खड़ा दिखाया। मोदी ने कहा, श्मैं भारत की जनता की ओर से हर खोई हुई जान के लिए गहरी संवेदना लेकर आया हूं और हर उस परिवार के लिए जिनका संसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बर्बर आतंकवादी हमले में टूट गया। हम आपका दर्द महसूस करते हैं। हम आपका दुख साझा करते हैं। भारत इजरायल के साथ मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ, इस पल में और उसके आगे भी खड़ा है। कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकता। कुछ भी आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता।श कितने सुविधाजनक तरीके से मोदी ने गजा में नेतन्याहू के इजरायली आतंकवाद का जिक्र तक नहीं किया। जबकि खुद इजरायल की जनता अपनी सरकार के ऐसे बर्बर रवैये के खिलाफ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी के भाषण पर उन्हें इतिहास की याद दिलाते हुए नेहरू के इजरायल के निर्माण पर आइंस्टीन को लिखे पत्र में व्यक्त विचारों का हवाला दिया। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया– अप्रैल 1955 में आइंस्टीन के निधन से कुछ समय पहले, आइंस्टीन और नेहरू ने परमाणु विस्फोटों और हथियारों के मुद्दे पर पत्रों का आदान–प्रदान किया था।श नेहरू ने 11 जुलाई 1947 को आइंस्टीन को जवाब में लिखारू श्मैं मानता हूं कि जबकि मेरी यहूदियों के लिए बहुत अधिक हमदर्दी है, मुझे अरबों की दुर्दशा के लिए भी उतनी ही हमदर्दी है। किसी भी घटना में, पूरा मुद्दा दोनों पक्षों की ओर से उच्च भावना और गहरे जुनून का हो गया है। नेहरू ने यहूदियों के नजरिए पर सवाल उठाते हुए कहारू श्मैंने फिलिस्तीन की इस समस्या पर अच्छा ध्यान दिया है और दोनों पक्षों द्वारा जारी की गई किताबों और पैम्फलेट्स को पढ़ा हैय फिर भी मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इसके बारे में सब जानता हूं, या मैं क्या किया जाना चाहिए पर अंतिम राय देने के लिए सक्षम हूं। मुझे पता है कि यहूदियों ने फिलिस्तीन में एक अद्भुत काम किया है और वहां के लोगों के स्तर को ऊं चा उठाया है, लेकिन एक सवाल मुझे परेशान करता है। इन सभी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बाद, वे अरबों की सद्भावना हासिल करने में क्यों विफल रहे? नेहरू ने लिखा–वे अरबों को अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ मांगों को मानने के लिए क्यों मजबूर करना चाहते हैं? नजरिए का तरीका ऐसा रहा है जो समझौते की ओर नहीं ले जाता, बल्कि संघर्ष की निरंतरता की ओर ले जाता है। मुझे कोई संदेह नहीं कि गलती एक पक्ष तक सीमित नहीं है बल्कि सभी ने गलती की है। मुख्य समस्या फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन की निरंतरता रही है। तो यहां जयराम रमेश ने इजरायल और फिलीस्तीन दोनों पर नेहरू जी के विचार बता दिए।

राशिफल

मेष :– किसी श्रेष्ठजन के प्यार से मन प्रसन्न होगा। किसी की कटु वाणी मन को दुखित कर सकती है। उच्च महत्वकांक्षाएं व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करेंगी। आलस्य कतई न करें।

बृषभ :– भौतिक महत्वकांक्षाएं अभाव का एहसास कराएंगी। परिजनों से कुछ भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। अच्छी योजनाओ द्वारा महत्वपूर्ण कायरें को समयानुकूल पूर्ण करेंगे।

मिथुन :– भावनाओं पर नियंतण्ररख अपने दायित्वों के प्रति सजग होना प्रगति का सूचक है। बचकाना स्वभाव महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाग्रता का अभाव पैदा करेगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में परिश्रम का लाभ मिलेगा।

कर्क :– महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। कुछ नयी आकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। भौतिक–सुख साधन में व्यय संभव। परिजनों से किसी प्रकार की शिकायत पर खुलकर बात करें।

सिंह :–भावना से उद्वेलित मन निकट संबंधों के सुख–दुख के प्रति चिंतित होगा। पूर्वाग्रहवश संबंधियों के प्रति नकारात्मकता को न पालें। भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं मन में नकारात्नक विचार ला सकती हैं।

कन्या :– पिता के सहयोग से मुश्किल दिनों में राहत मिलेगी। बालसुलभता व असंयमित शब्दों का प्रयोग संबंधों में कटुता लाएगा। आकस्मिक नई आशंकाओं से प्रभावित मन कोई गलत निर्णय ले सकता है।

तुला :– कुछ नयी अभिलाषाएं आपको उत्साहित करेंगी। शासन–सत्ता की दिशा में केंद्रित लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण दायित्व की पूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था हेतु मन चिंतित होगा।

वृश्चिक :– किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां अर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रेरित करेंगी। भावनाप्रधान मन रिश्तों से सहज ही प्रभावित हो जाता है।

धनु :– रोजगार क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं सार्थक होती हुई नजर आएंगी। श्रेष्ठजनों से नजदीकियां पैदा होंगी। व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ प्रबल इच्छाएं आपको उद्वेलित करेंगी।

मकर :– सामाजिक गतिविधियों में आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। अच्छी भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कुंभ :– पुरानी समस्याओं को हल कर सुख की अनुभूति करेंगे। शासन–सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पूजा–पाठ में पूरा दिन मन केंद्रित होगा। नये दायित्वों की पूर्ति होगी।

मीन :– नये संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। जीविका क्षेत्र में मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रयत्नशील होगा। रोजगार में व्यस्तता रहेगी किंतु जरूरी कार्य समय से पूर्ण करें।

दक्षिण एशिया सुरक्षा पर वाशिंगटन का आक्रामक रवैया भारत के लिए भी सिरदर्द

–नित्य चक्रवर्ती

12 फरवरी के राष्ट्रीय चुनाव में अपनी पार्टी की शानदार जीत के बाद बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बने हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। 60 साल के प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन में 17 साल के देश निकाला के बाद स्वदेश लौटे हैं, से उम्मीद की जा रही थी कि वे देश की खराब अर्थव्यवस्था और इसके प्रशासन को फिर से दुरुस्त करने को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, लेकिन उनके ध्यान का केन्द्र अचानक बदल गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया है और नई सरकार से चीन के खिलाफ रूख अपनाने के लिए कहकर बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। अमेरिका की तरफ से ऐसा खुला दावा हाल के महीनों में नहीं देखा गया है। असल में, अंतरिम सरकार के पहले के आधे समय में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी इतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन 12 फरवरी के चुनाव पास आते ही हालात बदल गए। बांग्लादेश को लेकर ट्रंप प्रशासन के नजरिए में अचानक बदलाव आया। नए अमेरिकी राजदूत ब्रेंटक्रिस्टेंसन ने इस साल 12 जनवरी को ढाका में अपना कार्यभार संभाला, अर्थात 12 फरवरी के चुनाव से ठीक एक महीना पहले। तब सेब्रेंट समेत अमेरिकी अधिकारी बीएनपी और जमात दोनों नेताओं को साध रहे हैं ताकि चीनी राजदूत योवेन को मात दी जा सके, जो पिछले तीन सालों से ढाका में सक्रिय हैं और सरकार और राजनीतिक पार्टियों के हर स्तर पर बड़े सम्पर्क बना रहे हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनके विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के पद संभालने के बाद, जो एक बहुत अनुभवी विदेश सेवा अधिकारी थे, ने हमेशा की तरह तीन बड़े देशों भारत, अमेरिका और चीन के साथ रिश्तों की पुनर्समीक्षा की और बांग्लादेश के फायदे के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर बात की। अभी–अभी घोषित अमेरिका–बांग्लादेश व्यापार समझौते की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। तीनों बड़े देशों के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने के मुद्दे दृष्टिपटल पर थे। जब शनिवार 21 फरवरी को शुरुआती बातचीत चल रही थी, तो अमेरिकी राजदूत ब्रेंटक्रिस्टेंसन ने बिना बांग्लादेश का नाम लिए एक कड़े बयान में कहा कि, वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते असर को लेकर परेशान हैं। ट्रंप की तरफ से तारिक को भेजे गए पत्र में यह भी कहा गया था कि अमेरिका–बांग्लादेश साझेदारी आपसी सम्मान और एक मुक्त और खुला भारत–प्रशांत को बढ़ावा देने में एक जैसे फायदे पर आधारित है। इसका असल में मतलब है कि अमेरिका अब चीन के खिलाफ अपनी भारत–प्रशांत सुरक्षा रणनीति में बांग्लादेश को एक भागीदार के तौर पर चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप ने अपनी चीन विरोधी सुरक्षा रणनीति में भारत को एक भागीदार के तौर पर शामिल किया है। इस प्रकार तारिक रहमान के लिए, अपनी स्थिति को स्थिर किये जाने से पहले ही, उन्हें अमेरिका की तरफ से यह धमकी मिल रही है कि अगर नई सरकार अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहती है, तो उसे चीन के खिलाफ अमेरिका की रणनीति का हिस्सा बनना होगा। जाहिर है, अगले दिन चीन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, जब चीनी दूत योवेन ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात की और कहा कि चीन बांग्लादेश की श्सर्वप्रथम बांग्लादेश नीतिय को मानने की घोषणा की तारीफ करता है और ढाका को चीन का सहयोग हर जगह होगा और यह किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। तारिक सरकार ढाका की धरती से अमेरिकी दूतावास के चीन विरोधी रवैये से बहुत शर्मिंदा है, लेकिन सरकार अमेरिका को बड़े भाई की भूमिका निभाने से रोकने के लिए बहुत कम काम ही कर सकती है। ढाका में राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश और चीन के बीच पिछले रक्षा समझौते से अमेरिका चिंतित है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश रक्षा सहयोग के लिए चीन के साथ अपनी भविष्य की बातचीत को आगे न बढ़ाए। जहां तक धारणा का सवाल है, बांग्लादेश के लोग ज्यादातर भारत और अमेरिका दोनों के खिलाफ भावनाएं रखते हैं। 5 अगस्त, 2024 को हसीना सरकार के गिरने के बाद से पिछले अठारह महीनों में, अमेरिका के लिए भावनाओं में गिरावट की तुलना में लोगों के बीच चीन का प्रभाव बढ़ा है। 2025 की शुरुआत में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉ. यूनुस के चीन दौरे में, बांग्लादेश के अलग–अलग जिलों में औद्योगिक क्षेत्र बनाने में चीन के निवेश में एक बड़ी कामयाबी मिली। बांग्लादेश में भारतीय सीमा के पास ड्रोन के लिए एक फैक्टरी लगाने का समझौता हुआ। तारिक सरकार से अब अमेरिका ने उस समझौते की नए सिरे से समीक्षा करने को कहा है। हाल ही में हस्ताक्षरित हुए अमेरिकी व्यापार समझौते की एकतरफा शर्तों ने दिखाया है कि कैसे नए बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान को वॉशिंगटन और बीजिंग के साथ रिश्तों को लेकर एक नाजुक संतुलन बनाने के चुनौतीपूर्ण कार्य से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों उनके देश में असर डालने की होड़ में हैं। एक तरफ, अमेरिका अपने बाजार तक पहुंच, सुरक्षा सहयोग और विनियामक लाभ का प्रचार कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन अवसंरचना, औद्योगिक समेकीकरण और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का वादा कर रहा है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और एक बड़ा अवसंरचनात्मक निवेशक बना हुआ है, जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक के परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है। अमेरिका बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और लंबे समय से इसका सबसे बड़ा विदेशी निवेशक रहा है, हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश (एफडीआई) स्टॉक तेजी से गिरा है। जून 2023 तक के वित्तीय वर्ष में लगभग 4 अरब डॉलर से गिरकर सितंबर 2025 तक यह लगभग 1 अरब डॉलर तक नीचे आ गया है, विशेषकर यूनुस राज के दौरान राजनीतिक उथल–पुथल और निवेशकों के कमजोर भरोसे की वजह से। सितंबर 2025 तक बांग्लादेश में चीनी एफडीआई स्टॉक लगभग 3 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। बीजिंग ने कई दूसरे कम विकसित देशों के साथ–साथ बांग्लादेशी निर्यात को शून्य–टैरिफ पहुंच भी दिया है। पहले 2022 में 98 प्रतिशत उत्पादनों को सीमाशुल्क–मुक्त पहुंच दिया और बाद में इस पेशकश को बढ़ाया। चीन बांग्लादेश को एक बड़ी रक्षा प्रणाली आपूर्तिकर्ता के तौर पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए बहुत उत्सुक है। अब ट्रंप प्रशासन इस पर एतराज कर रहा है। पहले के सालों में ऐसी स्थिति नहीं थी। बीजिंग बांग्लादेश में हो रहे विकासक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद डॉ. यूनुस से उनकी बैठक में मिले और बांग्लादेश के साथ रिश्ते बढ़ाने में व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई ताकि यह दक्षिण एशियाई देश चीनी मदद से अच्छी–खासी नौकरियां पैदा कर सके। चीन नहीं चाहेगा कि अमेरिका के दबाव की वजह से उसके समझौते रद्द हो जाएं। तारिक रहमान पर उनके सलाहकारों और थिंक टैंक की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है कि वे बांग्लादेश प्रथम नीति पर टिके रहें और बीएनपी चुनावी घोषणापत्र के मुताबिक बांग्लादेश की रणनीतिगत स्वायत्तता को ध्यान में रखकर काम करें। अगले कुछ दिन बताएंगे कि क्या तारिक में अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज करने और सिर्फ बांग्लादेश के हितों को ध्यान में रखकर काम करने की हिम्मत है?

पेंटागन ने ईरान के खिलाफ बड़े ऑप्रेशन के खतरे की चेतावनी दी

पेंटागन ईरान के खिलाफ लंबे मिलिट्री कैंपेन को लेकर प्रेसिडैंट ट्रम्प के सामने चिंता जता रहा है। उसने सलाह दी है कि जिन वॉर प्लान पर विचार किया जा रहा है, उनमें अमरीका और सहयोगी देशों के नुकसान, कमजोर एयर डिफैंस और जरूरत से ज्यादा फोर्स होने जैसे रिस्क हैं। मौजूदा और पुराने अधिकारियों ने कहा कि ये चेतावनियां ज्यादातर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने डिफैंस डिपार्टमैंट में और नैशनल सिक्योरिटी काऊंसिल की मीटिंग्स के दौरान दी हैं लेकिन पेंटागन के दूसरे लीडर्स ने भी ऐसी ही चिंताएं जताई हैं। ईरान पर हमलों के लिए जिन ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है, उनमें शुरुआती सीमित हमलों से लेकर सरकार को गिराने के मकसद से कई दिनों तक हवाई कैंपेन चलाना शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि सभी ऑप्शन में रिस्क होता है लेकिन खास तौर पर लंबे कैंपेन से अमरीकी सेना और हथियारों के स्टॉक पर काफी खर्च आ सकता है, अगर ईरान जवाबी कार्रवाई कर पाता है, तो इससे रीजनल पार्टनर्स की सुरक्षा मुश्किल हो सकती है। अगर अमरीका बड़ी मात्रा में एयर–डिफैंस हथियारों और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करता है, जिनकी आपूर्ति कम है, तो इससे चीन के साथ भविष्य में होने वाले संभावित झगड़े की तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है। अमरीका ने 2003 के ईराक युद्ध के बाद से मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा एयर पावर इकट्ठी की है, जिसमें एक एयरक्राफ्ट–कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी शामिल है। दूसरा कैरियर अब मेडिटेरेनियन में है। केन की चेतावनियों के बारे में मीडिया रिपोटर्स के बाद, ट्रम्प ने सोमवार को बाद में सोशल–मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, ''जनरल केन, हम सब की तरह, जंग नहीं देखना चाहेंगे लेकिन अगर ईरान के खिलाफ मिलिट्री लैवल पर जाने का फैसला होता है, तो उनकी राय है कि यह आसानी से जीता जा सकेगा।''ट्रम्प प्रशासन अभी भी ईरान के साथ एक संभावित डील पर बातचीत कर रहा है, जिससे अमरीका को उम्मीद है कि तेहरान के न्यूक्लियर वैपन की तरफ जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे, जिसे ईरानी नेताओं ने आगे बढ़ाने से मना कर दिया है, साथ ही उसके बैलिस्टिक–मिसाइल प्रोग्राम और हिजबुल्लाह और हमास जैसे रीजनल प्रॉक्सी मिलिशिया को उसके सपोर्ट पर रोक लगेगी। ईरान ने किसी भी अमरीकी हमले का जितना हो सके उतना कड़ा जवाब देने की धमकी दी है और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने पिछले हफ्ते कहा था कि उनकी सेना एक अमरीकी युद्धपोत को डुबो सकती है। किसी भी मिलिट्री ऑप्रेशन में जोखिम होता है लेकिन ईरान के खिलाफ लगातार अभियान शायद ट्रम्प द्वारा शुरू किए गए सबसे जटिल और खतरनाक मिलिट्री ऑप्रेशनों में से एक होगा, जिसमें अमरीका को मिडल ईस्ट में एक बड़े युद्ध में खींचने की क्षमता है। अधिकारियों के मुताबिक, ईरान पर किसी भी हमले के दौरान, कई बार बमबारी करने पर अमरीकी पायलट ईरानी एयर डिफैंस के लिए असुरक्षित हो सकते हैं। ईरानी मिसाइलें मिडल ईस्ट में मौजूद अमरीकी सैनिकों के बेस को निशाना बना सकती हैं। ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन से इसराईल में आबादी वाले सैंटर को भी निशाना बना सकता है, जैसा कि उसने पिछले जून में ईरान, इसराईल और अमरीका के बीच 12 दिन के युद्ध के दौरान किया था। कुछ अधिकारियों ने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि ईरान अपनी सरकार की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा और अमरीका के पास ईरानी मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही इंटरसैप्टर हैं।

बच्चों द्वारा ब्लेड से अपनी कलाई काटने की घटना पर प्रशासनिक जवाबदेही

–एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

भारत में स्कूली बच्चों की सुरक्षा –शिक्षा से आगे बढ़कर जीवन की रक्षा का राष्ट्रीय और वैश्विक दायित्व–वैश्विक स्तरपर भारत 142 करोड़ से अधिक आबादी वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इतनी विशाल जनसंख्या में करोड़ों बच्चे प्रतिदिन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। स्कूल केवल ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिकविकास और भविष्य की नींव का आधार होते हैं। ऐसे में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई घटनाएँ चाहे वह छत्तीसगढ़ के धमतरी जैसी दर्दनाक घटना हो या अन्य राज्यों में स्कूल परिसरों में हुई दुर्घटनाएँ,यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि अब केवल शिक्षा की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि सुरक्षा की समग्र व्यवस्था पर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानक लागू करने की आवश्यकता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि़ किसी भी सभ्य समाज की प्रगति का वास्तविक मापदंड उसके विद्यालयों की स्थिति और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा से निर्धारित होता है। विद्यालय केवल ज्ञान अर्जन का केंद्र नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की प्रयोगशाला होते हैं। यदि यह प्रयोगशाला ही असुरक्षित हो जाए तो राष्ट्र की नींव कमजोर हो जाती है। हाल के वर्षों में भारत के विभिन्न राज्यों से सामने आई घटनाएँ चाहे वह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की चौंकाने वाली घटना हो या अनेक राज्यों से जर्जर स्कूल भवनों के गिरने की खबरें,यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि अब समय आ गया है जब स्कूल सुरक्षा को शिक्षा नीति के पूरक तत्व के रूप में नहीं, बल्कि उसके मूल स्तंभ के रूप में स्थापित किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक बच्चों का जीवन और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित न हो। साथियों बात अगर हम छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में हाल में हुई घटना को समझने की करें तो,धमतरी जिले के कुरूद स्थित एक सरकारी स्कूल में 7वीं–8वीं कक्षा के 35 बच्चों द्वारा ब्लेड से अपनी कलाई काटने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह घटना केवल अनुशासन या प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है,बल्कि यह बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति,स्कूल वातावरण और सामाजिक संवाद की कमी की गंभीर चेतावनी है। जब काउंसलिंग में यह सामने आया कि बच्चों ने देखा–देखी में यह कदम उठाया, तो यह स्पष्ट हो गया कि किशोरावस्था में सामूहिक प्रभाव और आकर्षण की प्रवृत्ति कितनी तीव्र होती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है? क्या बच्चों को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का सुरक्षित मंच मिल रहा है?क्या शिक्षक औरअभिभावक उनके व्यवहार में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को समझ पा रहे हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है,तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिकताओं को पुनर्संतुलित करना होगा साथियों बात अगर हम 2 दिन पूर्व हाईकोर्ट द्वारा चिंता व्यक्त करने की करें तो,राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों पर चिंता व्यक्त करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने राज्य सरकार के बजट को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। यह टिप्पणी केवल एक राज्य तक सीमित समस्या नहीं दर्शाती, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में स्कूल भवनों की दयनीय स्थिति का प्रतीक है। जब भवनों की छतें कमजोर हों, दीवारों में दरारें हों, विद्युत तार खुले हों और शौचालय अनुपयोगी हों, तब बच्चों की सुरक्षा स्वतः खतरे में पड़ जाती है। बजट आवंटन और वास्तविक आवश्यकता के बीच की खाई को पाटना सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर मरम्मत, पुनर्निर्माण और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि सटीक जीवन रक्षा का कार्य है साथियों बात अगर हम इस मुद्दे को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो, विकसित देशों में भी स्कूल सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे तकनीकी और आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र में भी विद्यालयों में गोलीबारी की घटनाएँ समय–समय पर होती रही हैं। 2022 में टेक्सास के उवाल्डे स्थित रोब्ब एलिमेंटरी स्कूल में हुई गोलीबारी ने पूरी दुनियाँ को स्तब्ध कर दिया था। इससे पहले 1999 में कोलोराडो के कॉलम्बीने हाई स्कूल में हुई घटना ने स्कूल सुरक्षा पर वैश्विक बहस को जन्म दिया। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि आर्थिक समृद्धि और तकनीकी उन्नति अपने आप में सुरक्षा की गारंटी नहीं हैं। सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें जोखिम मूल्यांकन, निगरानी, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहयोग की निरंतर आवश्यकता होती है। भारत को इन अनुभवों से सीख लेकर अपने विद्यालयों के लिए बहु–स्तरीय अति महत्वपूर्ण सुरक्षा मॉडल विकसित करना चाहिए साथियों बात अगर हम भारत में शिक्षा का संचालन मुख्यतः राज्यों के अधीन है, इसको समझने की करें तो राष्ट्रीय स्तरपर नीति निर्माण में मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन की केंद्रीय भूमिका है। नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 ने शिक्षा की गुणवत्ता,समावेशिता और नवाचार पर जोर दिया है, परंतु सुरक्षा को एक स्वतंत्र और अनिवार्य स्तंभ के रूपमें संस्थागत रूपसे स्थापित करने कीआवश्यकता अभी शेष है। स्कूल सुरक्षा नीति को स्पष्ट दिशा–निर्देशों के साथ लागू किया जाना चाहिए, जिसमें भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, विद्युत मानक, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, सीसीटीवी निगरानी, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शामिल हों। प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य स्कूल सेफ्टी ऑडिट प्रणाली लागू की जानी चाहिए,जिसका वार्षिक नवीनीकरण हो और जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।जिला स्तर पर कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। यदि वे नियमित औचक निरीक्षण करें तो जमीनी स्तर की सच्चाई सामने आ सकती है। औचक निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सुरक्षा उपकरणों की कार्यशीलता, अग्निशामक यंत्रों की सर्विसिंग, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, आपातकालीन निकास मार्गों की उपलब्धता और खेल मैदानों की सुरक्षा का वास्तविक मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। कई बार स्कूलों में उपकरण तो लगे होते हैं, परंतु वे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर केवल कागजी प्रमाण किसी बच्चे का जीवन नहीं बचा सकते। इसलिए निरीक्षण प्रणाली को परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। साथियों बात अगर हम ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की स्थिति को समझने की करें तो यह विशेष चिंता का विषय है।कई स्कूल अस्थायी भवनों में संचालित होते हैं या दशकों पुराने ढाँचों में चल रहे हैं। वर्षा, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये भवन अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करते हैं।राज्य सरकारों को वार्षिक स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य करना चाहिए और जर्जर भवनों को तुरंत उपयोग से बाहर कर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। निजी विद्यालयों के लिए भी समान मानक लागू होने चाहिए। यदि कोई निजी संस्था सुरक्षा मानकों की अनदेखी करती है तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई जुर्माना, मान्यता निलंबन या निरस्तीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए।भौतिक संरचना के अतिरिक्त मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धमतरी की घटना ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की अनदेखी गंभीर परिणाम दे सकती है।विद्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलर नियुक्त किए जाने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में 'बाल संरक्षण समिति' का गठन हो और शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता तथा बाल अधिकारों पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाए। बुलिंग, शारीरिक दंड और लैंगिक उत्पीड़न के मामलों के लिए स्पष्ट शिकायत तंत्र हो। बच्चों को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।यह विश्वास ही सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव है। साथियों बात अगर हम स्कूल परिवहन भी सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है इसको समझने की करें तो, ओवरलोडेड बसें, अप्रशिक्षित चालक औरफिटनेस प्रमाणपत्र की अनदेखी अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त निरीक्षण अभियान अनिवार्य होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल बस में जीपीएस प्रणाली, फर्स्ट एड किट, अग्निशामक यंत्र और प्रशिक्षित परिचारक होना चाहिए। बस चालकों के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और पृष्ठभूमि सत्यापन भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा स्कूल के गेट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; घर से स्कूल और स्कूल से घर तक की पूरी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए,सामाजिक भागीदारी सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बना सकती है। अभिभावक–शिक्षक संघ को केवल परीक्षा परिणाम या शुल्क संरचना तक सीमित न रखकर सुरक्षा समीक्षा में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए।स्थानीय पुलिस, प्रशासन और समुदाय के बीच समन्वय सेसंदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई संभव है। स्कूल सेफ्टी कम्युनिटी नेटवर्क जैसे मॉडल विकसित किए जा सकते हैं, जहाँ समुदाय स्वयं निगरानी में सहयोग करे।डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभिभावकों को सुरक्षा रिपोर्ट और निरीक्षण निष्कर्ष उपलब्ध कराए जा सकते हैं। साथियों बात अगर हम स्कूल सुरक्षा को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है;इसको समझने की करें तो यह एक सामाजिक अनुबंध है जिसमें सरकार, शिक्षक,अभिभावक और समुदाय सभी सहभागी हैं। यदि किसी एक कड़ी में कमजोरी आती है तो पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन और निगरानी तक हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।यदि मुख्यमंत्री स्वयं समय–समय पर स्कूलों की सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठकें लें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करें, और आकस्मिक निरीक्षण करें, तो प्रशासनिक तंत्र में गंभीरता स्वतः आ जाती है। जब शीर्ष नेतृत्व संवेदनशील और सक्रिय होता है, तो निचले स्तर पर भी जवाबदेही बढ़ती है। बच्चों की सुरक्षा केवल शिक्षा विभाग का दायित्व नहीं, बल्कि गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का भी समन्वित उत्तरदायित्व है। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने स्कूल सुरक्षा को बहु–आयामी दृष्टिकोण से अपनाया है। आपदा प्रबंधन अभ्यास, नियमित मॉक ड्रिल, मनो वैज्ञानिक सहायता कार्यक्रम और सामुदायिक जागरूकता अभियान को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। भारत में भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों को विद्यालय स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। भूकंप, आग या अन्य आपात स्थितियों के लिए छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है ताकि संकट की घड़ी में घबराहट के बजाय संगठित प्रतिक्रिया हो। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि़ बच्चों की सुरक्षा केवल कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व है। जिस राष्ट्र में बच्चे सुरक्षित नहीं, वहाँ विकास की कोई भी परिकल्पना अधूरी है। धमतरी जैसी घटनाएँ चेतावनी हैं कि हमें शिक्षा के साथ–साथ सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख लेते हुए,स्थानीयआवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत नीतियाँ बनाकर और उनका कठोर क्रियान्वयन सुनिश्चित करके ही हम अपने विद्यालयों को वास्तविक अर्थों में सुरक्षित बना सकते हैं।जब प्रत्येक अभिभावक यह विश्वास कर सके कि उसका बच्चा विद्यालय में सुरक्षित है, तभी शिक्षा व्यवस्था पर समाज का भरोसा पूर्ण रूप से स्थापित होगा। यही विश्वास राष्ट्र की प्रगति की सबसे सुदृढ़ आधारशिला है।

त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग एवं बिना हेलमेट/सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाए
सभी अधिकारी फील्ड में रहे ड्यूटी पर तैनात, लोगों का फोन अवश्य उठाएं
लम्बी रूट वाली बसों में रखे जायें दो ड्राइवर
प्रत्येक रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाय –दयाशंकर सिंह

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। होली पर्व के अवसर पर आमजन की सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री जी द्वारा परिवहन विभाग/निगम के अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देशों के अनुपालन में परिवहन मंत्री द्वारा प्रदेश भर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त बैठक में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम प्रभु एन सिंह, परिवहन आयुक्त किंजल सिंह, विशेष सचिव परिवहन श्री खेमपाल सिंह उपस्थित रहे। परिवहन मंत्री ने होली पर्व के दृष्टिगत निर्देश दिए कि बसों की सुरक्षित यात्रा के साथ साथ बसों के फेरों की संख्या में वृद्धि की जाय, जिससे कि यात्रियों को सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा मुहैया कराते हुए उनके गन्तव्य तक पहुंचाया जा सके। 28 फरवरी से 09 मार्च की प्रोत्साहन अवधि के दौरान प्रारम्भिक दिवसों में दिल्ली से पूर्वी दिशा के यात्रियों को ले जाने हेतु अधिक से अधिक संख्या में बसें चलायी जायं, जो होली पर्व की सायं तक यात्रियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाती रहें। उन्होंने कहा कि लखनऊ एवं कानपुर नगरों में बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की जाय। होली के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों से मुख्यतः दिल्ली, जयपुर, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों को जाने हेतु पर्याप्त संख्या में बसें संचालित की जायं। प्रोत्साहन योजना अवधि में शतप्रतिशत निगम बसों को आनरोड किया जाय तथा निरंतर चलाये जाने की व्यवस्था आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जाय। परिवहन निगम की बसों में ईटीएम की शतप्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित रहे। कोई भी बस बिना ईटीएम के मार्ग पर संचालित न की जाय। परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि लम्बी दूरी की बसों में दो ड्राइवर अवश्य रखे जाएं, जिससे की यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करायी जा सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक निर्धारित रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन भी सुनिश्चित किया जाए। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवहन विभाग/निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाए। यात्रियों की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बस स्टेशनों एवं पार्किंग स्थलों पर शुद्ध खान–पान सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित किए जाए। वाहनों में ज्वलनशील सामग्री या गैस सिलेंडर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा और सभी वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि किसी वाहन को नियमों के उल्लंघन में निरुद्ध किया जाता है, तो यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम द्वारा तत्काल वैकल्पिक बसों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा ब्रेथ एनालाइजर से नियमित जांच की जाए। परिवहन मंत्री ने कहा कि आमजन को जागरूक करने के लिए सभी संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके अतिरिक्त, 24X7 नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने तथा आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी जांच टीमों के साथ फील्ड में तैनात रहेंगे। होली पर्व के अवसर पर सभी अधिकारी आमजन के फोन कॉल्स अवश्य उठाएंगे और उनकी समस्या का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित कराएंगे। अनफिट बसों का संचालन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली पर्व के अवसर पर परिवहन मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे होली का पर्व हर्षोल्लास एवं सौहार्द के साथ मनाएं, किन्तु यातायात नियमों का पालन अवश्य करें और सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता दें।

संक्षिप्त

यूपी में होली पर 4 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर

संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और छात्र–छात्राओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि होली के अवसर पर प्रदेश के स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर लगातार तीन दिनों तक बंद रहेंगे। आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, 2, 3 और 4 मार्च को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 1 मार्च को रविवार है इसलिए प्रदेश में लगातार चार दिनों तक अवकाश का माहौल रहेगा। हालांकि, छुट्टियों के इस लंबे अंतराल को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में एक विशेष बदलाव किया गया है। 28 फरवरी को कार्यदिवस घोषित किया गया है, ताकि वेतन संबंधी प्रक्रियाएं और जरूरी विभागीय कार्य समय से पूरे किए जा सकें। इसके बदले में सरकार ने 3 मार्च को विशेष अवकाश देने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों को अपने पैतृक निवास जाने और त्योहार मनाने में सुविधा होगी।मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की आर्थिक खुशियों का ध्यान रखते हुए यह भी निर्देश दिया है कि फरवरी माह का वेतन होली से पहले ही जारी कर दिया जाए। आदेश केवल नियमित कर्मचारियों के लिए ही नहीं, आउटसोर्सिंग कर्मियों, संविदाकर्मियों और सफाई कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगा। सीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

होली पर योगी सरकार का तोहफा, सभी कर्मचारियों का वेतन जारी करने के निर्देश, 3 मार्च को छुट्टी का ऐलान

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि होली से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन जारी कर दिया जाए और उन्होंने चेतावनी दी कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंगापुर और जापान की चार दिवसीय यात्रा से लौटने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने प्रशासन को कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि होली से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने अनुबंधित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और स्वच्छता कर्मियों का वेतन भी त्योहार से पहले जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को कार्यदिवस घोषित किया। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों को तीन मार्च 2026 को अवकाश दिया जाएगा। साथ ही, दो, तीन और चार मार्च को होली के अवकाश रहेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देशों के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने को कहा। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर और ऑटोमोबाइल विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया गया। सरकार ने इस यात्रा को 2029–30 तक राज्य को एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

योगी ने भरोसेमंद पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ाया

सलाहकार के रूप में चौथी बार एक्सटेंशन

संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब वह 28 फरवरी 2027 तक मुख्यमंत्री के सलाहकार बने रहेंगे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया गया है। रिटायर्ड आईएएस अवस्थी, मुख्यमंत्री योगी के करीबी अधिकारियों में गिने जाते रहे हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव पद से फरवरी 2022 में रिटायर होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके बाद लगातार चौथी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री के चार दिवसीय सिंगापुर और जापान दौरे पर भी वह उनके साथ रहे। शुक्रवार भोर में मुख्यमंत्री लखनऊ लौटे हैं। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी 31 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था। इसके लिए प्रशासन ने एक अस्थाई 'निःसंवर्गीय पद' का सृजन किया। पहली बार उन्हें फरवरी 2023 तक नियुक्त किया गया था, इसके बाद इसे बढ़ाकर फरवरी 2024 किया गया। फिर फरवरी 2025 और फरवरी 2026 तक सेवा विस्तार मिला। अब चौथी बार उन्हें फरवरी 2027 तक सेवा विस्तार मिला है। अवनीश अवस्थी ने उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक गृह विभाग संभाला।

2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया गया। उन्होंने सूचना विभाग, गृह विभाग और यूपीडा के सीईओ के रूप में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को गति देने में अहम भूमिका निभाई। गंगा एक्सप्रेसवे भी अब लगभग तैयार हो चुका है। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन प्रबंधन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भी उनकी विशेष भूमिका रही, जिसे काफी सराहा गया। चौथी बार सेवा विस्तार मिलने के साथ अब अवनीश अवस्थी के कंधों पर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य धरातल पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से सिंगापुर और जापान के दौरों से आए ढाई लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर लागू करना और औद्योगिक गलियारों को विकसित करना उनकी प्राथमिकता होगी। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले प्रदेश की बड़ी परियोजनाओं को पूरा कराने पर भी जोर रहेगा। शासन का मानना है कि उनकी निरंतरता से यूपी के विकास कार्यों की गति और प्रशासनिक समन्वय बना रहेगा।

48 घंटे से अधिक समय से बसपा विधायक के ठिकानों पर आईटी रेड, साथी ठेकेदार के यहां भी कार्रवाई

संवाददाता

लखनऊ। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी 48 घंटे से अधिक समय से जारी है। 25 फरवरी से शुरू हुई यह कार्रवाई लखनऊ, बलिया, सोनभद्र और कौशांबी तक हो रही है। शुक्रवार सुबह भी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित सीएसआईएल कार्यालय में आयकर अधिकारियों की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी रही। उमा शंकर सिंह के करीबी ठेकेदार के यहां भी छापेमारी चल रही है। विधायक की कंपनी 'छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड' (सीएसआईएल) का कार्यालय गोमतीनगर के बी–5/299, विपुल खंड में स्थित है। आयकर विभाग की जांच का केंद्र कंपनी से जुड़े वित्तीय लेन–देन और खनन कारोबार से संबंधित दस्तावेज बताए जा रहे हैं। 48 घंटे से अधिक समय से जारी इस कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आयकर विभाग किन निष्कर्षों पर पहुंचता है। बुधवार सुबह 50 से अधिक आयकर अधिकारी गाड़ियों के काफिले के साथ गोमतीनगर स्थित विधायक के आवास पहुंचे और पूरे परिसर को घेर लिया था। किसी को अंदर–बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। टीम ने घर और कार्यालय में रखी फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले। रेड की सूचना मिलते ही विधायक के समधी और पूर्व विधायक राकेश सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। गुरुवार को लखनऊ आवास पर छापेमारी बंद कर दी गई थी। लेकिन 48 घंटे से ऑफिस में जारी से है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज स्थित कंपनी कार्यालय पर आयकर की टीम 12 गाड़ियों में पहुंची। बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों पर शादी के पंपलेट लगे थे, जिससे संदेह न हो। यहां भी कई घंटों तक दस्तावेजों की जांच की गई थी। बलिया के रसड़ा स्थित विधायक के आवास पर भी मेन गेट बंद कर सर्चिंग की गई थी। इसके अलावा कौशांबी में उनके गिट्टी और बालू मिक्सिंग प्लांट पर आयकर विभाग ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों से पूछताछ की और रिकॉर्ड जब्त किए। सूत्रों के मुताबिक, अगस्त 2025 में आई सीएली रिपोर्ट में उनकी कंपनी पर 33,604 घनमीटर गिट्टी के अवैध खनन का आरोप लगा था, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के नुकसान की बात सामने आई थी। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर आयकर विभाग ने यह कार्रवाई शुरू की है। हालांकि, विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उमाशंकर सिंह बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। वे ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और हाल ही में अमेरिका से ब्लड चेंज कराकर लौटे हैं। फिलहाल लखनऊ स्थित आवास पर आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, टीम को करीब साढ़े 11 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा महंगी घड़ियां, सोना–चांदी और कीमती जेवर भी बरामद हुए हैं। बुधवार को आयकर टीम ने एक साथ 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग 1000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रहा है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर बरामदगी की पुष्टि नहीं की गई है। लखनऊ में बुधवार सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुई कार्रवाई आज सुबह 9 बजे तक चली। करीब 50 अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान किसी के भी अंदर–बाहर जाने पर रोक लगा दी गई थी। विधायक और उनका परिवार घर के अंदर ही मौजूद था। वहीं, सोनभद्र में छात्रशक्ति कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में 24 अधिकारी मौजूद हैं। गेट अंदर से बंद है। कंपनी के कर्मचारी भी भीतर हैं। रात में बाहर से खाना मंगवाकर अधिकारियों ने भोजन किया। बुधवार को अफसर बाराती बनकर पहुंचे थे। उनकी गाड़ियों पर शादी के पंपलेट लगे हुए थे। उमाशंकर सिंह, बलिया की रसड़ा विधानसभा से लगातार तीन बार विधायक हैं। उन्हें ब्लड कैंसर है। वे पिछले महीने ही अमेरिका से ब्लड चेंज कराकर लौटे हैं। फिलहाल, लखनऊ आवास पर आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस छापेमारी को मानवता के खिलाफ बताया था। योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह, उमाशंकर सिंह के समधी हैं। उन्होंने कहा– एक बेटी का बाप होने के नाते मैं उसके सुख–दुख में खड़ा रहूंगा। बेटी नहीं छोड़ी जा सकती, राजनीति छोड़ी जा सकती है। 2022 के शपथ पत्र के अनुसार, उमाशंकर सिंह की कुल संपत्ति करीब 54.05 करोड़ रुपए है। इसमें 18.05 करोड़ की चल और 35.99 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। उन पर 13 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। उमाशंकर सिंह राजनीति के साथ कारोबार की दुनिया में भी सक्रिय रहे हैं। उनकी 'छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन्स' नाम की कंपनी है, जो सड़क निर्माण का काम करती है। कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसके अलावा उनकी कंपनी माइनिंग सेक्टर में भी काम करती रही है। निर्माण और खनन के साथ वह शिक्षा और होटल कारोबार से भी जुड़े रहे हैं। उमाशंकर की पत्नी पुष्पा सिंह 'सीएस इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड' की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण से जुड़े काम करती है।

किसानों ने एलडीए के खिलाफ जमकर विरोध-प्रदर्शन किया

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयवाद ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के खिलाफ जमकर विरोध–प्रदर्शन किया। किसान हाथों में डंडा–झंडा और हसिया लेकर पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल महिला और पुरुष किसानों नारा लगाया जो ना माने झंडे से उसे समझाओ डंडे से। नाराज किसानों ने एलडीए के पुतले पर चोर लिखा। उसके बाद उसकी डंडों से पिटाई की। हसिया से काटा। किसान अपनी मांगों को लेकर एलडीए के मुख्य द्वार पर दरी बिछाकर बैठ गए हैं। किसान नेता अशोक यादव ने कहा किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। 40 वर्ष पूर्व 1984 में हमारी जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अधिकृत कर ली थी। उस समय 84 पैसे के हिसाब से मुआवजा तय हुआ। हम लोगों ने फिर वार्ता किया, तो मुआवजा 2.5 रुपए हुआ। कुछ लोग कोर्ट चले गए इसके बाद 4 रुपये 60 पैसे दर के हिसाब से तय हुआ। 2016 में अंतिम मोहरश्कोर्ट के द्वारा लगी की 4.60 पैसे सभी किसानों को दिया जाए, लेकिन एलडीए कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, इसलिए हम मुआवजा नहीं दे पाएंगे। जमीन अधिकृत करते समय विभिन्न प्रकार की सुविधा देने की बात कही थी। जिसमें मुख्य रूप से प्रत्येक परिवार को नौकरी, आवास, गांव का विकास और किसान भवन समेत तमाम चीजें शामिल थी। किसानों ने कहा कि लखनऊ का किसान आज दर–दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। 3 श्मशान स्थल थे, जिसमें से सिर्फ एक ही बचा है। एलडीए ने हमसे वादा किया था कि 400 चबूतरे विराज खंड में दिया जाएंगे जिस पर हमारे किसान भाई अपना रोजगार करेंगे। मगर एलडीए हमारे साथ धोखा किया मात्र 120 चबूतरे दिए वो भी दूसरे इलाके में। हमारे किसान परिवार की औरतें आज लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने पर मजबूर हैं। किसान प्रधान देश में अन्नदाता की यह स्थिति हो गई है कि दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। भूमि अधिग्रहण करते समय जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं हुआ। प्रशासन और एलडीए के अधिकारी मिलकर हमें गुमराह कर रहे हैं।प्रदर्शन कर रही राधा ने कहा कि आज हम लोग यहां से अपना अधिकार लेकर जाएंगे आर पार की लड़ाई के लिए आए हैं। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो गेट में ताला लगाकर अधिकारियों को कैद कर देंगे बैल भैंस की तरह। जैसे हमारे जानवरों को कैद किया जाता है इसी तरह हम अधिकारियों को कैद कर देंगे और इन्हें खाने के लिए चार भूसा देंगे। यह अधिकारी आए गेहूं और सरसों कटे तब पता चलेगा किसने की मेहनत क्या होती है। यह हमारा काम करके देखें हमेशा काम कर लेंगे हम हाल चाल लेते हैं।

अनाथालय के बच्चों को होली किट वितरित कर उनके साथ त्योहार की खुशियाँ साझा की

संवाददाता

लखनऊ। लुलु हाइपरमार्केट लखनऊ ने एक बार फिर आपसी एकता के मूल्यों को साकार करते हुए होली के पावन अवसर पर एक विशेष पहल की। "हैप्पी होली" अभियान के अंतर्गत लुलु हाइपरमार्केट की टीम ने श्रीमद दयानंद बालसदन अनाथालय के बच्चों को होली किट वितरित कर उनके साथ त्योहार की खुशियाँ साझा कीं। इस अवसर पर बच्चों के साथ उत्साह और मुस्कान का सुंदर संगम देखने को मिला। होली किट पाकर सभी बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम के दौरान टीम ने बच्चों के साथ समय बिताया और प्रेम, अपनत्व एवं साथ मिलकर त्योहार मनाने का संदेश दिया। यह पहल लुलु हाइपरमार्केट की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें हर त्योहार को समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर मनाने पर जोर दिया जाता है।लुलु समूह का मानना है कि सच्ची खुशी तब होती है जब उसे साझा किया जाए और हर चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय निदेशक दृ उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एवं दिल्ली, श्री नोमान अजीज खान ने कहा, "होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का अवसर है। लुलु हाइपरमार्केट हमेशा से एकता, प्रेम और साथ मिलकर आगे बढ़ने की भावना को प्रोत्साहित करता रहा है। बच्चों के साथ यह समय बिताना हमारे लिए बेहद विशेष और भावनात्मक अनुभव रहा।" वहीं, लुलु हाइपरमार्केट के जनरल मैनेजर श्री सुनील शर्मा ने कहा कि लुलु का प्रयास रहता है कि हर त्योहार को सभी के साथ मिलकर मनाया जाए। उन्होंने कहा, "खुशियाँ बाँटने से ही बढ़ती हैं, और लुलु परिवार इसी भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है।" लुलु हाइपरमार्केट आगे भी इसी प्रकार प्रेम, सौहार्द और सहभागिता की भावना को मजबूत करते हुए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहेगा।

लोकभवन के महिला ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाला, आग लगाने से पहले पुलिस ने पकड़ा

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार दोपहर हजरतगंज स्थित लोकभवन के गेट पर एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर तैनात के आत्मदाह दस्ते ने महिला को आग लगाने से पहले ही काबू में कर लिया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला अचानक लोक भवन के गेट के पास पहुंची। अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। इससे पहले कि वह आग लगा पाती, ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उसे थाने ले जाया गया। महिला की पहचान संध्या सिंह के रूप में हुई है। वह न्यू श्रीनगर मानकनगर की रहने वाली है। संध्या का मानक नगर क्षेत्र में जमीनी विवाद चल रहा है।

संध्या सिंह का आरोप उसकी जमीन पर इकबाल सिंह ने कब्जा किया है। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद इकबाल सिंह धमका रहा है। गालियां दे रहा है। उन्होंने स्थानीय पुलिस और तहसील प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

रोटरी क्लब लखनऊ का 89वां चार्टर डे एवं रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन डे समारोह सम्पन्न

संवाददाता

लखनऊ। रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ द्वारा 14 ।, रोटरी मार्ग, निराला नगर स्थित रोटरी भवन में 89वां चार्टर डे एवं रोटरी इंटरनेशनल के फाउंडेशन डे का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एनडी रोटेरियन मंकेश्वर पांडेय अपनी धर्मपत्नी सहित सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। क्लब द्वारा विशेष रूप से पद्मश्री सम्मान से अलंकृत प्रो. डॉ. रोटेरियन राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया। उनके सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर अभिनंदन किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ के अध्यक्ष रोटेरियन गणेश अग्रवाल ने की, जबकि संचालन सचिव रोटेरियन विभोर अग्रवाल द्वारा किया गया। अपने संबोधन में अध्यक्ष ने रोटरी के सेवा कार्यों, समाज के प्रति प्रतिबद्धता तथा मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ के पूर्व अध्यक्षों को उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

मोटोरोला ने अपने सभी सर्विस टचप्वाइंट पर लॉन्च किया नेशनवाइड मंथली सर्विस कनेक्ट और फ्री डोरस्टेप सर्विस

मोटोरोला 1 साल के भीतर अपना आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क दोगुना करने की तैयारी में

बीएनई

देहरादून। मोटोरोला, मोबाइल टेक्नोलॉजी में ग्ग्लोबल लीडर और भारत के प्रमुख AI स्मार्टफोन ब्रांड, ने आज अपना नेक्स्ट–जेनरेशन आफ्टर–सेल्स सपोर्ट इकोसिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की। यह कदम कंपनी की ग्राहक–प्रथम सोच और आसानी से मिलने वाली भरोसेमंद सक्रिय सेवा के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इस पहल के तहत, मोटोरोला हर महीने एक निर्धारित दिन को अपने अधिकृत सर्विस सेंटर्स और कलेक्शन पॉइंट्स पर नेशनवाइड मंथली सर्विस कैंप आयोजित करेगा, जो 28 फरवरी 2026 से शुरू होगा। नेशनवाइड मंथली सर्विस कैंप के दौरान ग्राहक कई विशेष लाभ उठा सकेंगे, जैसेरू जीरो लेबर चार्जेस, कोई इंस्पेक्शन या डायग्नोसिस फीस नहीं, फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट्स, मुफ्त डिवाइस क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन, बेसिक डिवाइस हेल्थ चेक–अप। इसके अलावा, ग्राहकों को एक्सेसरीज़ पर 10% छूट और स्पेयर पार्ट्स पर 10% छूट मिलेगी, जिससे डिवाइस की देखभाल अधिक किफायती, सुविधाजनक और पैसा वसूल हो जाएगी। यह पहल ग्राहकों के साथ लंबे समय तक संबंध मजबूत करने का एक समर्पित प्लेटफॉर्म भी बनेगी, जिसमें सक्रिय देखभाल और व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से जुड़ाव बढ़ेगा। सुविधा को और बढ़ाने के लिए, मोटोरोला फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस शुरू कर रहा है। इस सेवा के तहत टेक्निशियन या अधिकृत प्रतिनिधि ग्राहक के घर से डिवाइस ले जाएंगे, अधिकृत सर्विस सेंटर पर रिपेयर करेंगे और रिपेयर के बाद वापस पहुंचा देंगे। यह सेवा मोटोरोला सिग्नेचर, एज और रेज़र सीरीज़ के डिवाइसेज़ के लिए पूरी तरह मुफ्त है। सर्विस रिक्वेस्ट आसानी से की जा सकती है बस आपको https://en-in.support.motorola.com/app/mcp/contactus पर क्लिक करना होगा या फिर ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं, जिससे अनुभव पूरी तरह परेशानी–मुक्त रहेगा। तेज़, स्मार्ट और अधिक प्रीमियम सर्विस अनुभव देने के लिए डिज़ाइन की गई यह पहल एडवांस्ड AI–पावर्ड डिजिटल टूल्स, देशव्यापी फिजिकल सर्विस कवरेज और विशेष ग्राहक जुड़ाव लाभों को एक साथ लाती है। इस इकोसिस्टम का केंद्र एक व्यापक डिजिटल सेल्फ–सर्विस प्लेटफॉर्म है, जो डिवाइस हेल्प्य ऐप, सॉफ्टवेयर फिक्स्स टूल, इंटेलिजेंट वॉयस असिस्ट्टेंस (IVA), डवसप दृ मोटोरोला का AI चौटबॉट, और मजबूत ई–सपोर्ट पोर्टल से संचालित है। यह WhatsApp, वेब और डिवाइसेज़ पर 24X7 कई भाषाओं में सहायता उपलब्ध कराता है। यह टेक्नोलॉजी–फर्स्ट दृष्टिकोण मोटोरोला को भारत में उन चुनिंदा स्मार्टफोन ब्रांड्स में शामिल करता है जो ट्रूली AI–पावर्ड, हमेशा सक्रिय सर्विस इकोसिस्टम प्रदान करते हैं दृ जो समस्याओं को सक्रिय रूप से हल करता है, डिवाइस डाउनटाइम को कम करता है और सहज सपोर्ट अनुभव देता है। स्पीड और पहुंच के अलावा, मोटोरोला की नेक्स्ट–जेनरेशन सर्विस अनुभव सभी

टचपॉइंट्स पर बेहतर कम्फर्ट, पारदर्शिता और एकरूपता देने के लिए तैयार की गई है। ग्राहकों को संरचित सर्विस वर्कफ्लो, सरल डिजिटल चेक–इन, रियल–टाइम सर्विस अपडेट्स और सुव्यवस्थित इन–सेंटर प्रक्रियाओं का लाभ मिलता है, जिससे अधिक स्पष्टता, कम इंतजार का समय और कुल मिलाकर अधिक सहज सर्विस यात्रा सुनिश्चित होती है। इस डिजिटल–फर्स्ट अनुभव को तेज़ी से बढ़ते देशव्यापी सर्विस नेटवर्क का सपोर्ट मिलेगा, जो वित्त्त वर्ष 26–27 के अंत तक 1,200 से अधिक टचपॉइंट्स तक विस्तार करेगा दृ यह मौजूदा उपस्थिति में से दोगुने से अधिक की वृद्धि है, जो भारत भर में सुलभ और भरोसेमंद आफ्टर–सेल्स सपोर्ट के प्रति मोटोरोला की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अपनी ग्राहक–प्रथम फिलॉसफी के अनुरूप, मोटोरोला ने आफ्टर–सेल्स सर्विस फुटप्रिंट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और रिपेयर टर्नअराउंड टाइम (TAT) को काफी मजबूत किया है दृ मेट्रो, टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों में तेज़, अधिक विश्वसनीय और एकसमान सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए। आईडीसी की वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, मोटोरोला ने इंडस्ट्री में 8.3% मार्केट शेयर के साथ सबसे अधिक वर्ष–दर–वर्ष ग्रोथ 52.4% दर्ज की, जो ब्रांड की मजबूत गति और भारत में बढ़ते उपभोक्ता विश्वास को दर्शाता है। इस पहल के बारे में, टी. एम. नरसिम्हन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मोटोरोला इंडिया ने कहा, "मोटोरोला में हमारी ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता खरीदारी से कहीं आगे है। नेशनवाइड मंथली सर्विस कैंप और फ्री डोरस्टेप केयर सर्विस के लॉन्च के साथ, हम एक व्यापक, सक्रिय और सुलभ आफ्टर–सेल्स सपोर्ट इकोसिस्टम बना रहे हैं। AI–पावर्ड सर्विस टूल्स, तेज़ी से बढ़ते फिजिकल नेटवर्क और सार्थक ग्राहक जुड़ाव पहलों को मिलाकर, हमारा लक्ष्य्य सहज ओनरशिप अनुभव देना और लंबे समय तक ग्राहक विश्वास को मजबूत करना है।" सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इनोवेशन और देशव्यापी विस्तार में निरंतर निवेश के साथ, मोटोरोला भारत भर के ग्राहकों के लिए भरोसेमंद, सुलभ और श्रेणी में सबसे बेहतरीन आफ्टर–सेल्स अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मोटोरोला सर्विस टचप्वाइंट्स की जानकारी नीचे दी गई है :

Website Link – https://en-in.support.motorola.com/
Device Help App – Play Store Link
WhatsApp Chatbot – +91 8067916686 , +91 8067916687
rranty Check - https://en-in.support.motorola.com/app/warranty/check

मुनाफे के बावजूद जैक डॉर्सी की कंपनी ने 4,000 कर्मचारियों को निकाला, कैसे एआई बना फैसले का कारण

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक इंटेलिजेंस टूल्स के बढ़ते प्रभाव ने ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसी बदलाव का हवाला देते हुए, ट्विटर (अब एक्स) के सह–संस्थापक जैक डॉर्सी के नेतृत्व वाली वित्तीय तकनीकी कंपनी ब्लॉक ने अपने लगभग आधे कर्मचारियों की छंटनी करने का बड़ा फैसला लिया है। कंपनी के इस कदम से 4,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। डॉर्सी ने इसे कंपनी के इतिहास के सबसे कठिन फैसलों में से एक बताया है। मुनाफे के बावजूद छंटनी का फैसला क्यों? इस छंटनी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी किसी वित्तीय संकट से नहीं गुजर रही है। जैक डॉर्सी ने साफ किया है कि कंपनी का व्यवसाय मजबूत है, सकल लाभ लगातार बढ़ रहा है और मुनाफे में भी सुधार हो रहा है। दरअसल, कंपनी द्वारा बनाए और इस्तेमाल किए जा रहे इंटेलिजेंस टूल्स ने काम करने के तरीके को बदल दिया है। इन टूल्स की मदद से छोटी टीमें अधिक कुशलता और बेहतर तरीके से काम कर पा रही हैं। डॉर्सी का मानना है कि इस बदलाव को अपनाने में ब्लॉक ने कोई जल्दबाजी नहीं की है, बल्कि ज्यादातर कंपनियां इस मामले में पिछड़ गई हैंश। इस

कटौती के बाद, कंपनी का आकार 10,000 से अधिक कर्मचारियों से घटकर 6,000 से भी कम रह जाएगा। कंपनी ने छंटनी का एलान करते हुए क्या–क्या कहा?

बार–बार होने वाली छंटनी से कर्मचारियों के मनोबल और ग्राहकों के भरोसे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए कंपनी ने एकमुश्त छंटनी का विकल्प चुना। निकाले गए कर्मचारियों को वित्तीय सहायता देने के लिए कंपनी ने एक मजबूत सेवरेंस पैकेज का ऐलान किया हैः प्रभावित कर्मचारियों को 20 सप्ताह का वेतन और सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त सप्ताह का वेतन दिया जाएगा। मई के अंत तक की वेस्टेड इक्विटी और छह महीने की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। कर्मचारी अपने कॉरपोरेट डिवाइस अपने पास रख सकेंगे और ट्रांजिशन में मदद के लिए 5,000 डॉलर की अतिरिक्त राशि मिलेगी। अमेरिका के बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को भी स्थानीय नियमों के अनुसार समान सहायता प्रदान की जाएगी। अक्सर छंटनी के दौरान कंपनियों द्वारा कर्मचारियों का सिस्टम एक्सेस तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन ब्लॉक ने कर्मचारियों को ठीक से विदाई लेने का मौका देने के लिए गुरुवार शाम (पैसिफिक समय) तक स्लैक और ईमेल खुले रखने का फैसला किया है। इसके अलावा, डॉर्सी एक लाइव वीडियो सेशन के जरिए कर्मचारियों को धन्यवाद भी देंगे। उनका मानना है कि कुशल और ठंडे रवैये की तुलना में यह अजीब लेकिन मानवीय तरीका अपनाना बेहतर है।

संक्षिप्त

तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.3% रहने का अनुमान, महंगाई में कमी और मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था मजबूत

एजेंसी

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2025–26 की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत रहने की संभावना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिकूल बेस इफेक्ट के बावजूद देश की सकल घरेलू उत्पाद (ळक्च्) वृद्धि दर लगभग 8.3 प्रतिशत रह सकती है। किन कारकों ने जीडीपी को सहारा दिया? रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी दर में कटौती के बाद मांग और आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी ने ग्रोथ को सहारा दिया है। अनुमान के अनुसार, तीसरी तिमाही का जीडीपी ग्रोथ 8.3 प्रतिशत रह सकता है, जो पिछले साल की समान तिमाही के 6.4 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। सकल मूल्य वर्धन (GVA) वृद्धि दर में भी सुधार के संकेत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरी तिमाही में जीवीए ग्रोथ बढ़कर करीब 8.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 6.5 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि यह दूसरी तिमाही के 8.1 प्रतिशत के मुकाबले मामूली रूप से कम रह सकती है। नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर को लेकर क्या है संकेत? रिपोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर में कुछ नरमी आ सकती है। दूसरी तिमाही में 8.7 प्रतिशत रहने के बाद तीसरी तिमाही में यह घटकर लगभग 8.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 10.3 प्रतिशत थी। नाममात्र वृद्धि में यह कमी मुख्य रूप से घटती महंगाई के कारण जीडीपी डिफ्लेटर में आई गिरावट से जुड़ी मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 के लिए समग्र विकास परिदृश्य अभी भी लचीला और मजबूत बना हुआ है। साथ ही, शुरुआती संकेत बताते हैं कि वित्त वर्ष 2027 में भी आर्थिक गति जारी रह सकती है।

एनसीएल ने सतर्कता विभाग के तत्वावधान में सीएमपीएफ एवं सीएमपीएस विषय पर किया कार्यशाला का आयोजन

बीएनई

सिंगरौली। गुरुवार को कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने सतर्कता विभाग के तत्वावधान में मुख्यालय में सीएमपीएफ अधिनियम एवं कोल माइंस पेंशन योजना (सीएमपीएस) पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। निवारक एवं सहभागी सतर्कता के तहत आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य सीएमपीएफ अधिनियम एवं कोल माइंस पेंशन योजना के अनुपालन और क्रियान्वयन के दौरान आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करना, प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाना तथा संचालन स्तर पर सरलीकरण को बढ़ावा देना था। कार्यशाला को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए एनसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक बी. साईराम ने रचनात्मक सतर्कता की दिशा में आयोजित इस सार्थक पहल के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनसीएल तथा सतर्कता विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा उपायों को निरंतर सरल एवं उन्नत बनाना अपरिहार्य है। अपने उद्बोधन में उन्होंने सीएमपीएफ एवं सीएमपीएस प्रकरणों से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों से मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता के साथ गंभीरतापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। इस वर्ष को एनसीएल सहित कोल इंडिया लिमिटेड के लिए "सुधारों का वर्ष" बताते हुए साईराम ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में कंपनी के सामाजिक सुरक्षा ढांचे में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय आयुक्त–II (सतर्कता), कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (सीएमपीएफओ), धनबाद, भरत कुमार ए.वाई. ने सीएमपीएफ

अधिनियम के विकास, उसके विभिन्न चरणों, बीओटी के गठन तथा अधिनियम के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में निदेशक (वित्त) रजनीश नारायण, निदेशक (तकनीकी) आशुतोष द्विवेदी, मुख्य सतर्कता अधिकारी अजय कुमार जायसवाल तथा नवीन निश्चल, क्षेत्रीय आयुक्त, सीएमपीएफओ, सिंगरौली सहित सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक, मुख्यालय के विभागाध्यक्ष, स्टाफ अधिकारी (एचआर) तथा सभी क्षेत्रों एवं इकाइयों के सीएमपीएफ से संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। कार्यशाला को निदेशक (तकनीकी), एनसीएल, आशुतोष द्विवेदी तथा महाप्रबंधक (सतर्कता) उमाकांत यादव ने भी संबोधित किया। सत्र के दौरान सीएमपीएफ एवं सीएमपीएस से संबंधित विषयों पर मानव संसाधन/सीएमपीएफ विभाग द्वारा एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके अंतर्गत 'सी–केयर्स' पोर्टल के प्रदर्शन के साथ सीएमपीएफ सेटलमेंट, पेंशन, नामांकन, सीएमपीएफ कंट्रीब्यूशन , डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तथा शिकायत निवारण की प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। व्याख्यान एवं प्रस्तुतीकरण सत्र के उपरांत एक फीडबैक सत्र का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वागत भाषण एवं धन्यवाद ज्ञापन महाप्रबंधक (एचआर/सीएमपीएफ) प्रवेश कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सोने व चांदी में ज्यादा पैसे लगा सकेंगे निवेशक, सेबी ने लागू की नई व्यवस्था

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को म्यूचुअल फंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कुछ नई श्रेणियों की योजनाओं

को शामिल किया गया है और पोर्टफोलियो ओवरलैप पर अंकुश लगाया गया है। सोने–चांदी में अधिक निवेश की मंजूरी दी गई है। यह कदम नियामक के म्यूचुअल फंड नियमों को और सख्त बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। इसके तहत योजनाओं का स्पष्ट वर्गीकरण और मानकीकृत खुलासे किए जाएंगे। इससे भारत के तेजी से बढ़ते 900 अरब डॉलर के उद्योग में निवेशकों के हितों की सुरक्षा मजबूत होगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए नियमों के तहत, म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी स्कीमों में तय सीमा के निवेश के बाद बाकी बचे हिस्से को सोने और चांदी के साधनों में निवेश की अनुमति दी गई है। हाइब्रिड स्कीम सोने और चांदी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश कर सकते हैं। नए नियमों ने इक्विटी और हाइब्रिड स्कीमों में विशेष रूप से बाकी बचे हिस्से के भीतर कीमती धातुओं में निवेश को मानकीकृत कर दिया है। नए लाइफ–साइकल फंडों के तहत स्कीम्स सोने–चांदी के ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) में 10 फीसदी तक निवेश कर सकती हैं। नियमों में इन बदलावों से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सोने और चांदी को शामिल करने की प्रक्रिया अब औपचारिक हो गई है, जिससे निवेशकों को बहुमूल्य धातुओं का उपयोग मुख्य रूप से विविधीकरण के साधन के रूप में करने का एक विनियमित तरीका मिल गया है। सोने–चांदी के लिए हाजिर मूल्यों का उपयोग सेबी ने म्यूचुअल फंडों को निर्देश दिया कि वे एक अप्रैल, 2026 से अपने भौतिक सोने और चांदी के भंडार का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू स्टॉक एक्सचेंज के हाजिर मूल्यों का उपयोग करें। म्यूचुअल फंड अब उन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के हाजिर मूल्यों का उपयोग कर सकते हैं, जो भौतिक रूप से वितरित सोने और चांदी के डेरिवेटिव अनुबंधों का निपटान करते हैं।

क्यों शादी से डरती हैं डेजी शाह? करवाए अपने एग्स फ्रीज, कहा- परिवार शुरू करने के लिए शादी जरूरी नहीं

एजेंसी

डेजी शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शादी को डरावना बताया है और उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए परिवार शुरू करने के लिए शादी जरूरी नहीं है। साथ ही मां बनने को लेकर भी उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। आजकल शादी डरावनी लगती है फिल्मीग्यान को दिए एक इंटरव्यू में, 'जय हो' की एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवा लिए हैं, ताकि भविष्य में जब भी वे चाहें, वे मां बन सकें। उनका कहना है कि वे अपनी जिंदगी के फैसले अपनी शर्तों पर लेना चाहती हैं। डेजी ने माना कि आजकल रिश्तों से जुड़ी खबरें उन्हें परेशान करती हैं।

उन्होंने कहा, 'हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कपल्स के ब्रेकअप या वो 'ब्लू ड्रम' जैसे चौंकाने वाले मामले। ये सब बहुत डरावना है।' हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने शादी को लेकर ज्यादा सोचा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह शादी करेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह फैसला उन्होंने 'ऊपरवाले पर छोड़ दिया है।' क्या चुनेंगी डेजी...प्यार या पैसा? इंटरव्यू के दौरान जब उनसे 'प्यार' और 'पैसा' में से एक चुनने को कहा गया, तो 41 साल की एक्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें दोनों चाहिए। उनका मानना है कि रिश्ते में इमोशनल कनेक्शन के साथ–साथ आर्थिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है। वे चाहती हैं कि उनका पार्टनर खुद से आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र हो। परिवार शुरू करने के लिए शादी जरूरी नहीं मदरहुड पर बात करते हुए डेजी ने साफ कहा, 'परिवार शुरू करने के लिए शादी जरूरी नहीं है।' उन्होंने बताया कि उन्होंने एग फ्रीज करवाने का फैसला इसलिए लिया, ताकि वे जब भी चाहें, बच्चे कर सकें। वर्कफ्रंट वर्कफ्रंट की बात करें, तो डेजी शाह आखिरी बार वेब सीरीज श्रेड रूमश में नजर आईं थी। वे अब पलाश मुच्छल के निर्देशन में बनी फिल्म में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ श्रेयास तलपडे नजर आएंगे।

सुजीत कलकल ने बढ़ाया भारत का मान, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता

एजेंसी

नई दिल्ली। अंडर–23 विश्व चौंपियन सुजीत कलकल ने मुहामेट मालो 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों की 65 किग्रा फ्रीस्टाइल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। 23 साल के भारतीय पहलवान ने फाइनल में अजरबैजान

के राशिद बाबाजादे को 10–0 से हराया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जॉर्जिया के नीका जकाशविली को 10–0 से हराने और अल्बानिया के एंड्रियो अवदली पर 16–4 की जीत के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत करने के बाद सेमीफाइनल में अमेरिका के दो बार के पैन अमेरिकन चौंपियन जोसेफ मैककेना पर 11–0 से शानदार जीत हासिल की। क्रोएशिया में भी जीता था स्वर्ण इस महीने की शुरुआत में क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन जीतने के बाद, यह 2026 यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में सुजीत का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। सुजीत ने एंड्रियो अवदली पर 16–4 से जीत के साथ वार्म अप किया, जिन्होंने बाउट की शुरुआत में भारतीय खिलाड़ी को चार अंक पर पटक दिया था। नीका जकाशविली (जॉर्जिया) अगले 10–0 से हार गए, इससे पहले सुजीत ने जोसेफ मैककेना (अमेरिका) को 11–0 से हराया, यह स्कोर जाग्रेब ओपन के सेमीफाइनल जैसा ही था। 10–0 से राशिद को हराकर विजेता बने राशिद, जिन्होंने सेमीफाइनल में विटाली अरुजाउ (अमेरिका) के खिलाफ 16–13 से जीत हासिल की थी, वे फाइनल में मुकाबला नहीं कर पाए। सुजीत ने उन्हें 10–0 से हराकर लगातार दूसरा रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक जीता। कुल मिलाकर, यह यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज सर्किट में सुजीत का चौथा स्वर्ण पदक था। इससे पहले उन्होंने 2022 जैहैर शघायर और 2025 पोलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल में टॉप स्थान हासिल किया था। इसी कैटेगरी में हिस्सा ले रहे भारत के मोहित कुमार क्वालिफाइंग राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए। 57 किग्रा श्रेणी में अंकुश और आतिश टोडकर ने कांस्य पदक तक पहुंचने के लिए रेपेचेज में मुकाबला किया, लेकिन अपने–अपने मैचों में हार गए। इस बीच, सुमित (57 किग्रा), राहुल (61 किग्रा), सिद्धार्थ (70 किग्रा), परविंदर (74 किग्रा), और आर्यन (86 किग्रा) अपने–अपने वेट डिवीजन में मेडल राउंड तक पहुंचने में नाकाम रहे। भारत ने मुहामेट मालो 2026 के लिए 48 सदस्यों की कुश्ती टीम भेजी थी, जिसमें पुरुषों की फ्रीस्टाइल, महिलाओं की डिवीजन और ग्रीको–रोमन कैटेगरी में 16–16 लोग शामिल थे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743